



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 13, 2011/ज्यैष्ठ 23, 1933

No. 122]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 13, 2011/JYAISTA 23, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2011

विषय : चीन जन. गण. तथा जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 14/7/2011-डीजीएडी.—यतः मै. टैक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (प्रा.) लि. ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निधारण) नियम, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् पाटनरोधी नियम कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य और जापान (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

घरेलू उद्योग और स्थिति

2. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मै0 टैक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (प्रा0) लि0, मुम्बई (जिसे एतदपश्चात् आवेदक कहा गया है) द्वारा दायर किया गया है। कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक का हिस्सा प्रमुख है और कुल भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक है। अतः आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

3. मौजूदा जाँच में विचाराधीन उत्पाद डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स (जिसे एतदपश्चात "डिजिटल प्लेट्स" अथवा संबद्ध वर्स्तु कहा गया है) है। मुद्रण उद्योग में डिजिटल प्लेट्स का इस्तेमाल डाटा को कागज अथवा टिन शीट या पॉलीफिल्म्स आदि जैसी गैर अवशोषक सामग्री पर एक छवि (डॉट पैटर्न या टेक्स्ट) के रूप में अंतरित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल प्लेट्स का इस्तेमाल करने वाली मुद्रण प्रक्रिया में डिजिटल वर्कफ्लो छवि के "कम्प्यूटर से प्लेट" पर सीधे अंतरण को संभव बनाता है जबकि समानान्तर वर्कफ्लो में छवि के अंतरण के लिए मध्यवर्ती फिल्म अपेक्षित होती है।

डिजिटल प्लेट्स रासायनिक कोटिंग युक्त उच्च शुद्धता वाली लिथो-ग्रेड एल्यूमीनियम कॉयल्स से बनी होती हैं। डिजिटल प्लेट्स पॉजिटिव (नॉन एक्सपोज्ड भाग छवि निर्माण करता है) अथवा नेगेटिव (एक्सपोज्ड भाग छवि निर्माण करता है) वर्किंग प्लेट्स होती हैं। अलग-अलग प्रकार की प्लेटों के लिए कोटिंग संधटक जिन्हें "सेन्सिटाइजर्स" के नाम से भी जाना जाता है, अलग-अलग होते हैं।

डिजिटल प्लेटों को मूल रूप से उनके अनुप्रयोजन के आधार पर दो श्रेणियों यथा वॉयलट और थर्मल प्लेट्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे डिजिटल प्लेट्स जिन्हें दृश्य तथा अधिकांशतः दृश्य प्रकाश ऊर्जा (वॉयलट लेजर्स) के इस्तेमाल द्वारा एक्सपोज किया जाता है, वॉयलट प्लेट्स कहलाती हैं। इसी प्रकार वे डिजिटल प्लेट्स जिन्हें इनक्रा-रेड ऊर्जा के जरिए एक्सपोज किया जाता है, थर्मल प्लेट्स कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त सीटीसीपी प्लेट्स ("कम्प्यूटर-टु-कन्वेन्शनल प्लेट") के नाम से जानी जाने वाली कुछ चुनिंदा प्रकार की डिजिटल प्लेट्स होती हैं जिनमें एक्सपोजर तथा छवि को कम्प्यूटर से सीधे प्लेट पर अंतरित करने के लिए पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। सभी आकास-प्रकार की सभी प्रकार की डिजिटल प्लेट्स विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं।

संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ की टैरिफ मद "8442.5020" के अंतर्गत शामिल है। तथापि 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.9191 और 7606.9290 जैसे अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी संबद्ध वस्तु का आयात हुआ है। ये सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से मौजूदा जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

शामिल देश

4. मौजूदा आवेदन चीन जन.गण. और जापान (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में दर्ज किया गया है।

समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु जिसका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के सदृश है। पाटित उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, प्रकार्यों अथवा अंतिम प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदकों ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित और आपर्त वस्तु तथा भारत में आयातित संबद्ध वस्तु का प्रयोक्ता उद्योग द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा रहा है।

अतः मौजूदा जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

सामान्य मूल्य

जापान

6. आवेदक ने यह सूचित किया है कि जापान के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत का साक्ष्य जुटाने के हर संभव प्रयास किए गए थे। तथापि आवेदक जापान में वास्तविक घरेलू बिक्री कीमत का ऐसा कोई भी साक्ष्य प्राप्त करने में अक्षम रहा है जिसे मौजूदा जाँच के प्रयोजनार्थ सटीक एवं समुचित साक्ष्य माना जा सके।

अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण एल्यूमीनियम की एलएमई कीमतों, घरेलू उद्योग के खपत मानदण्डों, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर जापान में प्रचलित उपयोगिता कीमतों, घरेलू उद्योग के अनुभवों के अनुसार बिक्री, प्रशासनिक तथा वित्तीय व्ययों सहित अन्य परिवर्तन लागतों तथा एक समुचित लाभ मार्जिन के आधार पर किया गया है।

चीन जन.गण.

7. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा उन्होंने पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। आवेदक ने एलएमई कीमतों, घरेलू उद्योग के खपत मानदण्डों, घरेलू उद्योग के अनुभवों के अनुसार बिक्री, प्रशासनिक तथा वित्तीय व्ययों सहित अन्य परिवर्तन लागतों तथा एक समुचित लाभ मार्जिन के आधार पर परिकलित सामान्य मूल्य का दावा किया है।

निर्यात कीमत

8. आवेदक ने एग्जिमनेट द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदेवार आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का दावा किया है। कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़े एवं समुद्री बीमा में समायोजन का दावा किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

पाटन मार्जिन

9. कारखाना द्वारा स्तर पर सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना की गई है, जिसमें दोनों संबद्ध देशों के मामलों में अत्यधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। यह माना गया है कि इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य, कारखाना द्वारा निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

10. आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने अत्यधिक हानि, वस्तु-सूची में वृद्धि, लगाई गई पूंजी पर आय तथा नकद लाभ में कमी के कारण वास्तविक क्षति का सामना किया है। आवेदक ने प्रतिकूल कीमत प्रभाव का भी दावा किया है जैसा कि कीमत अवमूल्यन, कीमत ह्रास, कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री से प्रदर्शित होता है। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई। प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आवेदक को हुई "क्षति" के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जो पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं।

पाटनरोधी जांच शुरू करना

11. उपर्युक्त पैराग्राफों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वर्ताओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। अतः प्राधिकारी एतद्वारा किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी नियमों के नियम-5 के संदर्भ में कथित पाटन एवं उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच शुरू करते हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

12. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 (12 महीने) है। तथापि क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल, 2007 से जांच अवधि के अंत तक की अवधि अर्थात वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 (पीओआई) की अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारें, भारत के ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से निम्नलिखित पते पर लिखित में जांच से संगत निवेदन कर सकता है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 243,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

समय सीमा

14. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए।

ज्ञात निर्यातक एवं आयातक, जिन्हें अलग से लिखा जा रहा है, को भी उनको अलग से लिखे पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

15. सभी हितबद्ध पक्षकार उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई गोपनीय सूचना के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में एक अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे। गोपनीय सूचना का अगोपनीय अंश अथवा अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत हो जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की एक अर्थपूर्ण समझ प्राप्त हो सके। यदि सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त पैराग्राफ में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रस्तुत करने वाला सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है अथवा सामान्य या सारांश रूप में उसका प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

16. नियम 6(7) के अनुसारण में प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

२१९२ ६२/११-२

असहयोग

17. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2011

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Digital Offset Printing Plates originating in or exported from China PR and Japan.

F. No. 14/7/2011-DGAD.—M/s. Technova Imaging Systems (P) Ltd. has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as AD Rules) for initiation of anti-dumping duty investigation concerning imports of “Digital Offset Printing Plates” (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from China PR and Japan.

DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

2. The application has been filed by M/s TechNova Imaging Systems (P) Ltd, Mumbai (hereinafter referred to as the applicant) on behalf of the domestic industry. The production of the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production of the like article and is more 50 % of total Indian production. The applicant thus satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present investigation is Digital Offset Printing Plates (hereinafter referred to as “Digital Plates” or subject goods). Digital Plates are used in the printing industry for transferring data as an image (dot patterns or text) onto paper or on non-absorbent substrates like tin sheets or poly films, etc. In the printing process using digital plates, the digital workflow enables direct transfer of image from a ‘computer to the plate’ using lasers unlike the analogue workflow that requires an intermediary film to transfer the image.

Digital plates are made from high-purity litho-grade aluminium coils coated with a chemical coating. Digital plates may be either positive (non-exposed area forms image)

or negative (exposed area forms image) working plates. The coating components, also known as 'sensitizers' vary for different types of plates.

Digital plates may be broadly classified into two categories namely violet and thermal plates based on their application. Digital plates that are exposed using visible and near-visible light energy (violet lasers) are called violet plates. Similarly, digital plates that are exposed using infra-red energy are called Thermal plates. In addition, there are certain types of digital plates known as CtCP Plates ('Computer-to-Conventional Plate') that use ultra violet rays for exposure and transferring image directly from the computer to the plates. All types of digital plates in all dimensions are covered within the scope of the product under consideration.

The subject goods fall under Tariff Item '8442.5020' of the Customs Tariff. However, there have been imports of the subject goods under other headings such as 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.9191 and 7606.9290 as well. Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

COUNTRIES INVOLVED

4. The present application has been filed in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR and Japan (hereinafter referred to as subject countries).

LIKE GOODS

5. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable. The applicants have claimed that goods produced and supplied by them and the subject goods imported into India are being interchangeably used by the user industry.

Therefore, subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'like article' to the goods being imported from the subject countries for the purpose of the present investigation.

NORMAL VALUE

JAPAN

6. The applicant has submitted that all possible efforts were made to get evidence of the price at which the subject goods are being sold in the domestic market of Japan. However, the applicant has not been able to get any evidence of actual domestic selling price in Japan which can constitute accurate and adequate evidence for the purpose of the

present investigation. The normal value has, therefore, been determined based on estimates of cost of production taking international raw material prices. Accordingly, normal value has been determined based on LME prices of aluminium, consumption norms of the domestic industry, utilities prices prevailing in Japan based on publicly available information, other conversion costs including selling, administrative and financial expenses as per domestic industry's experience and a reasonable profit margin.

CHINA PR

7. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the AD Rules. The applicant has claimed Constructed Normal Value based on LME prices of aluminium, consumption norms of the domestic industry, conversion costs including selling, administrative and financial expenses as per domestic industry's experience and a reasonable profit margin.

EXPORT PRICE

8. The applicant has claimed export price of the subject goods from the subject countries based on the transaction wise import data provided by the Eximnet. Adjustments have been claimed on account of ocean freight and marine insurance to arrive at ex-factory export price. There is sufficient evidence of the export price for the subject goods from the subject countries.

DUMPING MARGIN

9. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of each of the subject countries. It is considered that there is, *prima facie*, evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

INJURY AND CAUSAL LINK

10. The applicant has claimed that they have suffered material injury by way of increased losses, increase in inventories, decline in return on capital employed and cash profits, etc. The applicant has also claimed adverse price effects as evidenced by price depression, price suppression, price undercutting and price underselling. The applicant has claimed that the material injury has been caused due to the dumped imports from the subject countries. The Authority considers that there is sufficient evidence of 'injury'

being suffered by the applicant caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

11. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, holds that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied would be adequate to remove injury to the domestic industry.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

12. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2010 to 31st March 2011 (12 months). However, the period for injury examination would cover periods from 1st April 2007 to the end of the POI i.e. 2007-08, 2008-09, 2009-10 and 2010-11(POI).

SUBMISSION OF INFORMATION

13. The known exporters in the subject countries and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority,
 Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
 Ministry of Commerce & Industry,
 Department of Commerce,
 Room No. 243, Udyog Bhavan,
 New Delhi – 110011**

TIME LIMIT

14. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of

publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within 40 days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

15. All interested parties shall provide a non-confidential summary in terms of Rule 7(2) of the AD Rules for the confidential information provided by them. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in the above paragraph, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

16. In terms of Rule 6(7), the Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

NON COOPERATION

17. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority